

पब्लिक हेल्थकेयर इंफ्रा के लिए भारत को 1 अरब डॉलर देने का वादा

प्रासंगिकता: जीएस-2: द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और भारत से जुड़े और भारत के हितों को प्रभावित करने वाले समझौते, भारत और उसके पड़ोसी-संबंध।

मुख्य वाक्यांश: विश्व बैंक, हेल्थकेयर, पीएम-एबीएचआईएम, आईबीआरडी, महामारी, जीवन प्रत्याशा, मृत्यु दर, जूनोटिक रोग, कल्याण।

संदर्भ:

- केंद्र सरकार और विश्व बैंक ने देश के स्वास्थ्य क्षेत्र के विकास को समर्थन देने और बढ़ाने के लिए प्रत्येक \$500 मिलियन के दो पूरक ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं।



मुख्य विचार:

- विश्व बैंक \$1 बिलियन के संयुक्त वित्तपोषण के माध्यम से भारत के प्रमुख प्रधानमंत्री-आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम-एबीएचआईएम) की सहायता करेगा।
- अक्टूबर 2021 में लॉन्च किया गया, आयुष्मान भारत मिशन का उद्देश्य पूरे देश में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे को बढ़ाना है।
- दो ऋण इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट (आईबीआरडी) से उत्पन्न हुए हैं और इनकी अंतिम परिपक्वता अवधि 18.5 वर्ष है, जिसमें 5 वर्ष की छूट अवधि शामिल है।

7 राज्यों में सेवा:

- विश्व बैंक ने कहा कि, राष्ट्रीय स्तर की पहलों के अलावा, एक ऋण आंध्र प्रदेश, केरल, मेघालय, ओडिशा, पंजाब, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवा वितरण को प्राथमिकता देगा।
- भविष्य की महामारियों के खिलाफ देश की स्वास्थ्य प्रणालियों का लचीलापन और तैयारियों को बढ़ाने के भारत के फैसले का समर्थन दो परियोजनाएं कर रही हैं।
 - यह परियोजनाओं में भाग लेने वाले राज्यों की आबादी के लिए बहुत फायदेमंद होगा और अन्य राज्यों के लिए सकारात्मक स्पिलओवर उत्पन्न करेगा।

प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन

- 1 फरवरी, 2021 को, वित्त वर्ष 2025-2026 तक छह साल की अवधि के लिए 'आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना' (पीएमएएसबीवाई) का नाम बदलकर 'पीएम-आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन' (पीएम-एबीएचआईएम) कर दिया गया।
- इस योजना के तहत उपाय प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक जैसे सभी स्तरों पर देखभाल की निरंतरता में स्वास्थ्य प्रणालियों और संस्थानों की क्षमता विकसित करने और वर्तमान और भविष्य की महामारियों/आपदाओं के प्रभावी ढंग से जवाब देने के लिए स्वास्थ्य प्रणालियों को तैयार करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं।
- **पीएम-एबीएचआईएम योजना के घटक:**
 - **केंद्र प्रायोजित घटक:**
 1. 10 उच्च फोकस वाले राज्यों में 17,788 ग्रामीण स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों के लिए सहायता।
 2. सभी राज्यों में 11,024 शहरी स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र स्थापित करना।
 3. 11 उच्च फोकस वाले राज्यों में 3382 ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट। XV वित्त आयोग स्वास्थ्य क्षेत्र अनुदान और एनएचएम के तहत अन्य राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए सहायता।
 4. सभी जिलों में एकीकृत जन स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं की स्थापना।
 5. 5 लाख से अधिक जनसंख्या वाले सभी जिलों में क्रिटिकल केयर अस्पताल ब्लॉक स्थापित करना।
 - **केंद्रीय क्षेत्र के घटक:**
 1. 150 बिस्तर वाले क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक के साथ 12 केंद्रीय संस्थान प्रशिक्षण और परामर्श स्थलों के रूप में;
 2. राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (एनसीडीसी), 5 नए क्षेत्रीय एनसीडीसी और 20 महानगरीय स्वास्थ्य निगरानी इकाइयों का सुदृढीकरण;
 3. सभी सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं को जोड़ने के लिए सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में एकीकृत स्वास्थ्य सूचना पोर्टल का विस्तार;
 4. 17 नई सार्वजनिक स्वास्थ्य इकाइयों का संचालन और प्रवेश के बिंदुओं पर 33 मौजूदा सार्वजनिक स्वास्थ्य इकाइयों का सुदृढीकरण, जो कि 32 हवाई अड्डों, 11 बंदरगाहों और 7 लैंड क्रॉसिंग पर है;
 5. 15 स्वास्थ्य आपातकालीन संचालन केंद्र और 2 कंटेनर आधारित मोबाइल अस्पताल स्थापित करना; और

- वन हेल्थ के लिए एक राष्ट्रीय संस्थान, वायरोलॉजी के लिए 4 नए राष्ट्रीय संस्थान, डब्ल्यूएचओ दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के लिए एक क्षेत्रीय अनुसंधान मंच और 9 जैव-सुरक्षा स्तर III प्रयोगशालाओं की स्थापना।

जीवन प्रत्याशा:

- विश्व बैंक ने अनुमान लगाया है कि भारत की जीवन प्रत्याशा 1990 में 58 से बढ़कर 2020 में 69.8 हो गई है, जो इसके आय स्तर के औसत से अधिक है।
- इसके अतिरिक्त, पांच वर्ष से कम आयु की मृत्यु दर (36 प्रति 1,000 जीवित जन्म), शिशु मृत्यु दर (30 प्रति 1,000 जीवित जन्म), और मातृ मृत्यु दर (103 प्रति 100,000 जीवित जन्म) सभी भारत के आय स्तर के औसत के अनुरूप हैं।
- कोविड-19 महामारी ने आवश्यक सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यों के लिए पुनरोद्धार, सुधार और क्षमता विकसित करने और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और व्यापकता में सुधार के महत्व पर प्रकाश डाला है।

दो कार्यक्रम:

- महामारी तैयारी कार्यक्रम के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली, जिसका बजट 500 मिलियन डॉलर है, "संभावित अंतरराष्ट्रीय चिंता की महामारी" की प्रभावी ढंग से पहचान करने और रिपोर्ट करने के लिए देश की निगरानी प्रणाली को लैस करने के लिए सरकार की पहल में सहायता करेगा।
 - यह तुरंत प्रकोप का जवाब देगा, और जूनोटिक रोगों सहित रोगजनकों के उद्भव को रोकेगा।
- इसके विपरीत, 500 मिलियन डॉलर के बजट वाला एन्हांस्ड हेल्थ सर्विस डिलीवरी प्रोग्राम, एक पुनर्गठित प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा मॉडल के माध्यम से स्वास्थ्य सेवा वितरण में सुधार करके सरकार के प्रयासों को बढ़ावा देगा, जिससे प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाओं तक घरेलू पहुंच बढ़ेगी।
 - कार्यक्रम स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों के लिए राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानकों के प्रमाणीकरण का समर्थन करके देखभाल की गुणवत्ता में भी सुधार करेगा, और यह राज्यों के बीच कार्यान्वयन क्षमता, प्रदर्शन माप और ज्ञान के आदान-प्रदान को मजबूत करेगा, जिससे स्वास्थ्य क्षेत्र के शासन और जवाबदेही में बदलाव आएगा।

निष्कर्ष

- कोविड-19 महामारी एक स्पष्ट अनुस्मारक थी कि महामारी की तैयारी एक वैश्विक सार्वजनिक भलाई है और दुनिया भर में महामारी की तैयारी और स्वास्थ्य प्रणाली में सुधार की महत्वपूर्ण आवश्यकता को प्रकाश में लाया गया है।

- संभावित महामारी का सामना करने के लिए स्वास्थ्य प्रणाली की क्षमता को मजबूत करने के अपने फैसले में दोनों परियोजनाएं भारत की सहायता कर रही हैं।
 - इस निर्णय का परियोजनाओं में भाग लेने वाले राज्यों के व्यक्तियों पर महत्वपूर्ण लाभकारी प्रभाव पड़ेगा और साथ ही अन्य राज्यों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्र. प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. इस योजना का उद्देश्य प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक देखभाल सहित सभी स्तरों पर स्वास्थ्य प्रणालियों और संस्थानों की क्षमताओं को बढ़ाना है, ताकि वर्तमान और भविष्य की महामारियों और आपदाओं का प्रभावी ढंग से जवाब दिया जा सके।
2. मिशन महानगरीय क्षेत्रों में ब्लॉक, जिला, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर निगरानी प्रयोगशालाओं का एक नेटवर्क विकसित करके एक आईटी सक्षम रोग निगरानी प्रणाली बनाने का लक्ष्य रखता है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

- a) केवल 1
- b) केवल 2
- c) 1 और 2 दोनों
- d) इनमें से कोई भी नहीं

उत्तर: (c)

व्याख्या:

प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन:

- 1 फरवरी, 2021 को, वित्त वर्ष 2025-2026 तक छह साल की अवधि के लिए लगभग 64,180 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ 'आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना' (पीएमएसबीवाई) का नाम बदलकर 'पीएम-आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन' (पीएम-एबीएचआईएम) कर दिया गया। इस योजना को कैबिनेट ने 15 सितंबर, 2021 को हुई बैठक में मंजूरी दी थी। यह योजना राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अतिरिक्त है।
- इस योजना के तहत उपाय प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक जैसे सभी स्तरों पर देखभाल की निरंतरता में स्वास्थ्य प्रणालियों और संस्थानों की क्षमता विकसित करने और वर्तमान और भविष्य की महामारियों / आपदाओं के प्रभावी ढंग से जवाब देने के लिए स्वास्थ्य प्रणालियों को तैयार करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। (विकल्प 1 सही है)।
- मिशन का लक्ष्य मेट्रोपॉलिटन क्षेत्रों में ब्लॉक, जिला, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर निगरानी प्रयोगशालाओं का एक नेटवर्क विकसित करके और प्रभावी ढंग से पता लगाने, जांच करने, रोकने और सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थिति और रोग के प्रकोप का मुकाबला करने के लिए प्रवेश के बिंदुओं पर स्वास्थ्य इकाइयों को मजबूत करके एक आईटी सक्षम रोग निगरानी प्रणाली का निर्माण करना है।

हल: दोनों कथन सही हैं इसलिए सही विकल्प (c) है

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्र. विशेष रूप से प्रधान मंत्री-आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम-एबीएचआईएम) के संबंध में विश्व बैंक से ऋण भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र के विकास में किस प्रकार सहायता और वृद्धि करेगा? टिप्पणी 150 शब्द)

स्रोत: Business Line



ध्येय IAS
most trusted since 2003